भारतीय गणतंत्र का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सफर अत्यंत गौरवशाली और संघर्षपूर्ण रहा है जहाँ अनेकता में एकता हमारी सबसे बड़ी और अद्वितीय पहचान है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत हमारे दूरदर्शी नेताओं ने 26 जनवरी 1950 को एक ऐसा लिखित संविधान लागू किया जो विश्व का सबसे विस्तृत और संप्रभुता संपन्न दस्तावेज माना जाता है। इस महान संविधान के अंतर्गत 395 मूल अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं जिन्हें बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का कड़ा परिश्रम लगा था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने कृषि और औद्योगीकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। वर्ष 1965 और 1966 के भयंकर सूखे के बाद देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ जिसने हमारे राष्ट्र को खाद्यान्न उत्पादन में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बना दिया। वर्तमान परिदृश्य में जब हमारी कुल जनसंख्या 1.43 अरब के अनुमानित आँकड़े को पार कर चुकी है तब यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि हम आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता का अधिकतम उपयोग करें। आज भी हमारे देश की 55 प्रतिशत से अधिक आबादी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और उससे संबद्ध वाणिज्यिक गतिविधियों पर ही निर्भर करती है। इसी कारणवश किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में निरंतर वृद्धि की गई है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक कृषकों के बैंक खातों में 6000 रुपये की वार्षिक आर्थिक सहायता सीधे स्थानांतरित की जा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने संपूर्ण विश्व में अपना उत्कृष्ट परचम लहराया है। 24 सितंबर 2014 को मंगलयान का पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित होना और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर तथा विक्रम लैंडर का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित अवतरण भारत की अभूतपूर्व तकनीकी दक्षता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन जटिल अंतरिक्ष मिशनों को मात्र 615 करोड़ रुपये के अत्यंत किफायती बजट में पूर्ण करके हमारे वैज्ञानिकों ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया जिसने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार करते हुए एक राष्ट्र एक कर की मजबूत अवधारणा को मूर्तरूप प्रदान किया है। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया 24 जुलाई 1991 को आरंभ हुई थी जिसने हमारे देश को विदेशी निवेश और वैश्वीकरण के लिए पूरी तरह खोल दिया। सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में हमारे उत्साही युवाओं ने अपनी विलक्षण प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व की अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों विशेषकर सौर और पवन ऊर्जा की ओर तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं ताकि वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य के स्तर पर लाया जा सके। ढाँचागत विकास की बात करें तो 15500 करोड़ रुपये से अधिक के भारी निवेश से राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तारीकरण और भारतीय रेलवे का शत प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा रहा है। परंतु इस तेज़ आर्थिक विकास और बढ़ते शहरीकरण के साथ साथ हमें कुछ गंभीर वैश्विक चुनौतियों का भी